

प्रेषक,

डी0एस0 गर्बाल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष,

राजस्व परिषद उत्तराखण्ड,
देहरादून।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. आयुक्त,

गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 27 जुलाई, 2016

विषय-गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिये गये भूमि पट्टों के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में निवासरत् अनेक व्यक्तियों/परिवारों को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि के पट्टे दिये गये हैं। पट्टे की शर्तों के अनुसार इन्हें संबंधित भूमि पर विशिष्ट प्रयोजन के अनुरूप कार्यवाही करने एवं भूमि धारित करने के आनुवंशिक अधिकार प्राप्त हैं। इन पट्टाधारकों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि इन्हें संबंधित भूमि का मालिकाना हक दिया जाये, जिससे उन्हें भूमि के विक्रय के अधिकार भूमि के सदुपयोग हेतु भूमि को बंधक रखकर बैंकों से ऋण लेने एवं अन्य उपयोगी लाभ प्राप्त हो सके।

इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य की भूमि के ऐसे पट्टेदार जिन्हें गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत पट्टे दिये गये हैं, को पट्टों की शर्तों में संशोधन करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन उन्हें मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। ये शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

- 1- संबंधित पट्टा दिनांक 01.06.2016 से 30 वर्ष या इससे अधिक पूर्व दिया गया हो एवं इसकी भूमि उसी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी जा रही हो, जिस प्रयोजन के लिए तत्समय पट्टा दिया गया था।
- 2- उपरोक्त शर्त को पूर्ण करने की स्थिति में दिनांक 09.11.2000 को लागू सर्किल रेट के 1/20 के आधार पर प्रीमियम जमा कराने के लिए निर्गत आदेश की तिथि से एक वर्ष तक शासन के पक्ष में जमा करने की स्थिति में संबंधित पट्टेदार को उसके पट्टे की भूमि पर मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार प्रदान किया जाय।
- 3- ऐसा अधिकार भूस्वामी द्वारा अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में विहित एवं उल्लिखित अधिकतम भूमि की सीमा तक (सिंचित भूमि-12.5 एकड़, असिंचित भूमि 18 एकड़) के लिए ही दिया जाय।
- 4- उपरोक्त व्यवस्था केवल गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अंतर्गत दिये गये पट्टों के संदर्भ में ही लागू होगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु करने का कष्ट करें तथा उक्त कार्यवाही प्रत्येक पक्ष में शिविर लगाकर की जाय तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उसका नियमित अनुश्रवण/समीक्षा मासिक रूप से करते हुए समीक्षा आख्या निर्धारित प्रपत्र पर राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गब्र्याल)
सचिव।

पृ०संख्या- J 767/XVIII(II)/2016-02(01)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 7. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।